

कंक्रीट के जंगलों के बीच अनुकूल निर्माण जरूरी...

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर केंद्रित दो दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार का किया शुभारंभ



पीडब्ल्यूडी और आईआईटी इंदौर के बीच निर्माण तकनीक के विकास पर केंद्रित एमओयू का हुआ आदान-प्रदान

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कंक्रीट के बढ़ते विस्तार और घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर केंद्रित दो दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार का शुभारंभ किया।

लोक निर्माण विभाग और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रकृति आधारित स्थापत्य हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, जिसे आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने मांडव के जल प्रबंधन और नगर नियोजन का उदाहरण देते हुए ऐसे आयोजनों

को ऐतिहासिक स्थलों तक ले जाने की बात कही। सीएम ने राजा भोज की स्थापत्य परंपरा और समरांगण सूत्रधार का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की आवश्यकता है। भोपाल के बड़े तालाब और उज्जैन में शिप्रा नदी क्षेत्र की संरचनाओं को भी उन्होंने उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ग्लोबल वॉर्मिंग गंभीर चुनौती बन चुकी है। राज्य में गुढ़ी पड़वा से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जल संरक्षण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।

(शेष पेज 8 पर)

कंक्रीट के जंगलों के बीच अनुकूल...

सस्टेनेबल फ्यूचर केवल विचार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है: राकेश सिंह- लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में सभी नए निर्माण कार्य ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आधारित किए जा रहे हैं। विभाग ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया है। हाईवे और फ्लाईओवर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जा रहा है। उन्होंने विशेषज्ञों से कम लागत वाली तकनीक विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, सस्टेनेबल फ्यूचर केवल विचार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, जिसे अभी से लागू करना होगा।

पीडब्ल्यूडी और आईआईटी इंदौर के बीच समझौता- कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग और आईआईटी इंदौर के बीच निर्माण तकनीक के विकास को लेकर एमओयू का आदान-प्रदान हुआ।

लोक निर्माण विभाग ने बनाई अपनी नई छवि- आईबीसी के पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक रोशनी, वेंटिलेशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस, 3डी प्रिंटिंग और प्री-फैब्रिकेशन जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा। प्रमुख अभियंता एसआर बघेल ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग निर्माण तेजी से बढ़ रहा है और इससे लोक निर्माण विभाग की नई पहचान बनी है।